



सं.: 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 22 सितंबर, 2020

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) <u>MUMBAI – 400 051.</u>	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001 Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, <u>MUMBAI – 400 001.</u>
--	--

विषय: सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में सूचना

महोदय/महोदय,

पीएफसी को एफपीओ के लॉन्च करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों की वापसी खरीद विकल्प (बाय बैक ऑप्शन) और बढ़े हुए लिक्विडिटी पैकेज पर अपडेट से संबंधित बाजार में प्रसारित हाल ही के समाचारों पर प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार, सेबी के विनियम 30 के अनुसार (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के रूप में हाल के घटनाक्रम पर पीएफसी के विचार संलग्न हैं।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत
धन्यवाद

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्तमान घटनाक्रमों पर अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

इन अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ, हमने अपनी कंपनी से संबंधित वर्तमान के कुछ घटनाक्रमों पर पीएफसी के दृष्टिकोण को साझा करने का प्रयास किया है।

1) क्या पीएफसी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) की योजना बना रहा है?

पीएफसी द्वारा एफपीओ के लॉन्च पर बाजार में अफवाहें फैल रही हैं। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीएफसी निकट भविष्य में ऐसे किसी भी एफपीओ को लॉन्च करने की योजना नहीं बना रहा है।

इसके अतिरिक्त, यह भी बताया जाता है कि 30 जून 2020 तक, पीएफसी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.11% के पूंजी टीयर-1 के साथ 17.32% है। इस प्रकार, हमारे पास 15% की विनियामक सीमा से अधिक पर्याप्त कुशन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी द्वारा डिस्कॉम लिक्विडिटी पैकेज के अंतर्गत ऋण दिए जाने से, हमें राज्य सरकार की गारंटी के कारण कम जोखिम भार का फायदा होगा। इससे हमारी पूंजी का अधिक दक्षता से लाभ उठाने में मदद मिलेगी। वर्तमान पूंजीकरण प्रोफाइल को देखते हुए, हम मानना है कि पीएफसी का पूंजी स्तर हमारे परिसंपत्ति पक्ष के जोखिमों और भविष्य की वृद्धि के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, पीएफसी फिलहाल पूंजी वृद्धि के लिए किसी भी अपेक्षा की परिकल्पना नहीं कर रहा है।

2) क्या पीएफसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों की वापसी खरीद (बायबैक) पर विचार कर रहा है?

पीएफसी द्वारा पहले से जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड पर इसके द्वारा बायबैक/एग्जिट विकल्प के लॉन्च के संबंध में बाजार में कुछ जानकारी प्रसारित की गई है। यह बताया जाता है कि अब तक, पीएफसी ने न तो किसी नए बायबैक/एग्जिट विकल्प की पेशकश की है और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सहित अपने बॉण्ड इश्यू पर ऐसे बायबैक/एग्जिट विकल्प के ऑफर के लिए किसी एजेंसी की नियुक्ति की है। इस प्रकार, बॉण्ड इश्यू की मौजूदा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बायबैक/एग्जिट विकल्प निवेशक के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, इन बॉण्डों के मूलधन और ब्याज चुकौती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमारी समझ के अनुसार, लोटस सिक्योरिटीज द्वारा सेकंडरी बाजार में खरीद शुरू की गई है। इस प्रकार, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार के पत्राचार पर सावधानी बरतें।

3) दिनांक 30 जून 2020 तक एसईबी(यों) की बकाया राशि को कवर करने के लिए पीएफसी द्वारा संवर्धित फंडिंग का प्रबंधन कैसे किया जाएगा?

सितंबर 2020 में, सरकार ने 30 जून 2020 तक अपनी बकाया राशि के क्लीयरेंस के लिए डिस्कॉम (मों) को संवर्धित फंडिंग की अनुमति प्रदान कर दी है। संवर्धित हिस्से के लिए ऋण को पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी द्वारा समान रूप से वित्त-पोषित किया जाएगा।

हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता लगभग 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ रुपए होगी।

पीएफसी को इस वित्तीय वर्ष में लिक्विडिटी की दृष्टि से बेहतर स्थान पर रखा गया है, पीएफसी ने घरेलू बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों पर लगभग 58,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है जिसमें 11,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी इंजेक्शन पैकेज के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के लिए 70% ऋण बाध्यता अपेक्षा को पूरा कर लिया गया है। पीएफसी की उच्च साख और विविधकृत निधीयन अवसरों जैसे बॉण्ड ईटीएफ, विदेशी बाजार इत्यादि की उपलब्धता पर विचार करते हुए, हमारा मानना है कि पीएफसी बाजार के इन स्रोतों से आसानी से राशि जुटाने में सक्षम होगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार का एक महत्वपूर्ण भागीदार होने के नाते, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पीएफसी को अपेक्षित सहायता में वृद्धि की है। हमें विश्वास है कि सरकार इस योजना के लिए भी अपनी सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।
